Item of Manufacture	Annual capacity
1, Steel ingots/billets	1,50,000 Tonnes
2, Rolled products like rounds and flats	1,30,000 Tonnes

उत्तर प्रदेश में निरक्षरता

*240. **मौलाना अबदुल्ला खान आजमी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में निरक्षरता कितने प्रतिशत है ;

(ख) इस समय उत्तर प्रदेश में निरक्षरता कितने प्रतिशत है ; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निरक्षरता दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश और उत्तर प्रदेश में, 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाली जनसंख्या के संबंध में निरक्षरता की दर क्रमश: 47.89 प्रतिशत और 58.29 प्रतिशत थी ।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण जिसमें अनौपचारिक शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, शामिल हैं, जिसका उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15–35 वर्ष की आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में निरक्षरता उन्मूलन के व्यापक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है । इस उद्देश्य की प्राप्त के लिए राज्य में जो विशेष उपाय किए गए हैं। किए जा रहे हैं, वे निम्न प्रकार हैं :

(i) साक्षरता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु गांधीवादी और सर्वोदय के कार्यकर्ताओं की टीमों द्वारा 43 जिलों में 1755 जत्थे आयोजित किए गए । जिनमें 35000 गांवों को शामिल करते हुए इस प्रक्रिया में लगभग 3.00 लाख स्वयंसेवकों का पता लगाया गया । इसी तरह, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक स्वैच्छिक एजेंसी भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने राज्य भर में जत्थे आयोजित किए ।

(ii) फतेहपुर, मेरठ और सोनभद्र (चार ब्लाक) जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किये गये । कुछ और जिलों को भी ऐसे अभियानों में शीघ्र ही शामिल किए जाने की संभावना है ।

(iii) नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा राज्य के 25 जिलों में 4700 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं ।

(iv) राज्य में 12726 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और 104 जन शिक्षण निलयमों को चलाने के लिए अभी तक 136 स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की गई है ।

(v) नव साक्षरों को उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2108 जन शिक्षण निलयमों (ज० शि० नि०) की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिनमें से 1608 जन शिक्षण निलयमों के चालू होने की सूचना मिली है ।

(vi) क्षेत्र विशेष, समयबद्ध और लागत प्रभावी बनाने के लिए परंपरागत, केन्द्र आधारित कायक्रम को पुनर्गठित किया गया है ।

(vii) सभी 895 ब्लाकों में 65,388 प्राथमिक स्कूलों को आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है ।

(viii) राज्य में 63,375 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को भी संस्वीकृति-प्रदान कर दी गई है । ये केन्द्र, सरकारी तथा स्वैच्छिक दोनों प्रकार की एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे हैं ।

Review of dual pricing policy on fertilizers

@1471. SHRI V. NARAYANASAMY:
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have undertaken or propose to undertake a review of its dual pricing policy on Fertilizers; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) and (b) Scheme on Fertilizer Subsidy for Small and Marginal Farmers has been taken up in 1991-92, and there is no specific proposal at present, under consideration, to review the dual pricing policy for the current year.

Small and Marginal Farmers

@@1472. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the number of small and marginal farmers identified so far in the country for distribution of fertilizers at subsidised rates; and

(b) what is the quantity and value of fertilizer distributed to them upto 31st October, 1991?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPALLY RAMACHANDRAN): (a) As per the Agriculture Census 1985-86, the number of small and marginal farmers in the country are 179.22 lakh and 561.47 lakh respectively.

The amount of Central assistance allocated to different States/UTs was based on the area operated by small and marginal farmers, as well as the average per ha. consumption of the State/UT.

(b) The quantity and value of fertilizer distributed to small and marginal farmers upto 31st October, 1991 is not yet available.

Brackish water fisheries

1473. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal for promoting brackish water fisheries;

(b) if so, the steps Government have taken in that direction in Orissa during the last three years;

(c) whether Government have sought external assistance for implementing brackish water fishery projects in that State; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Yes, Sir.

(b) Some of the steps taken by the Government for promotion of Brackish water Aquaculture in Orissa during the last three years include:

(i) establishment of a prawn farm at Mouza Jamboo in Cuttack district;

@Previously Unstarred Question 655, transferred from the 28th November, 1991.

@@Previously Unstarred Question 650, transferred from the 28th November, 1991.